

भूटान-चीन संबंध: भारत के लिये नहितिरथ

यह एडिटोरियल 25/10/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Warming ties: On Bhutan-China relations and India's concerns" लेख पर आधारित है। इसमें भूटान के विदेश मंत्री की हालिया चीन यात्रा के नहितिरथों के संबंध में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), दक्षणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सारक), बंगल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आरथिक सहयोग पहल (बमिस्टेक), नवीकरणीय उरजा, वन संरक्षण, टकिअू पर्यटन।

मेन्स के लिये:

भारत-भूटान संबंध, बढ़ते चीन-भूटान संबंधों के बारे में चतिएँ और भारत पर उनका प्रभाव, उभरते चीन-भूटान संबंधों पर भारत की प्रतक्रिया

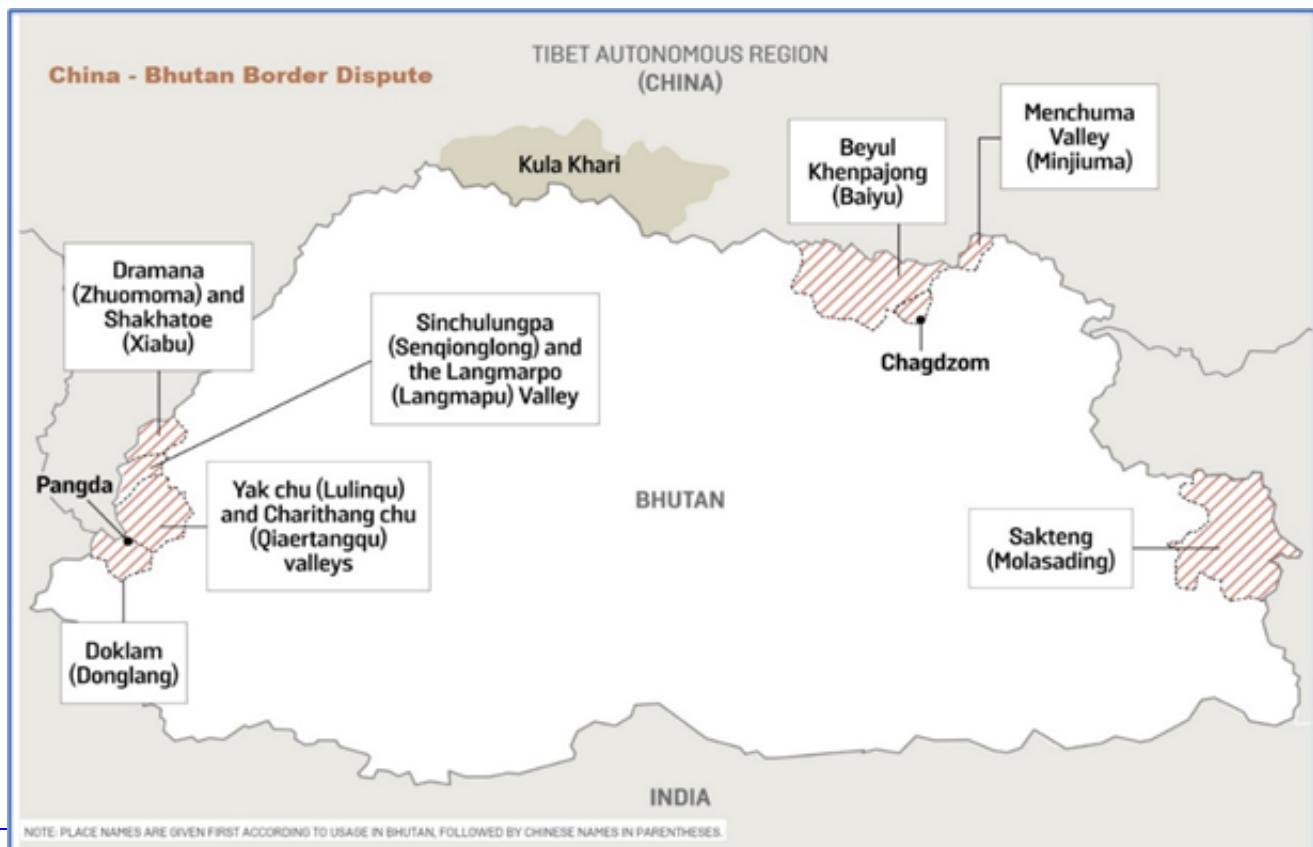
हाल ही में भूटान के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया जसे विभिन्न स्तरों पर अभूतपूर्व माना जा रहा है क्योंकि भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं और यह यात्रा कसी भूटानी विदेश मंत्री की पहली चीन यात्रा थी।

चीन और भूटान ने बीजागी में सीमा वारता के 25वें दौर का आयोजन किया और "भूटान-चीन सीमा के परसीमन और सीमांकन पर संयुक्त तकनीकी टीम (JTT) के उत्तरदायतिव एवं कार्य" (Responsibilities and Functions of the Joint Technical Team (JTT) on the Delimitation and Demarcation of the Bhutan-China Boundary) पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह सीमा समाधान के लिये वर्ष 2021 में शुरू किये गए उनके त्रांचिरणीय रोडमैप को आगे बढ़ाता है जो वर्ष 2016 में उनकी अंतिम वारता के बाद से बने सकारात्मक माहौल पर आधारित है।

- इस त्रांचिरणीय रोडमैप में सर्वप्रथम सीमा पर सहमति के विषय को विचारारथ रखना; फिर ज़मीनी स्तर स्थलों का दौरा करना; और फिर औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन करना शामिल है।

इस यात्रा को लेकर भारत की क्या चतिएँ हैं?

- भूटान के साथ भारत के अद्वतीय संबंध ने उसे भूटान द्वारा चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में सतरक कर दिया है।
- भारत की चितिओं के बावजूद परतीत होता है कि भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रबल संभावना है।
 - हालाँकि, भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत को आश्वस्त भी किया था कि चीन के साथ कसी भी समझौते से भारत के हतिं को क्षति नहीं पहुँचेगी।
- भारत पर भूटान की अद्वतीय नारिभरता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के अपने प्रयासों में भारत को भरोसे में लिया होगा और भारत के सुरक्षा सुरक्षा हतिं एवं 'रेड लाइन' (वह सीमा जिसके पार नहीं जाया जा सकता) का पालन करने की गारंटी दी होगी।
 - ऐसी एक रेड लाइन में चीन को दक्षणी डोकलाम की चोटियों से दूर रखना शामिल है जो भारत के 'सलीगुड़ी कॉरडियर' के नकिट है। उल्लेखनीय है कि भूटान और चीन उत्तर की घाटियों में और पश्चिम में डोकलाम पठार पर अपने क्षेत्रों के बीच अदला-बदली पर विचार कर रहे हैं।
 - एक दूसरी रेड लाइन यह है कि सीमा वारता को आगे बढ़ाने के क्रम में चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और स्थायी चीनी राजनयिक उपस्थितिके लिये स्वयं को खोलने के मामले में भूटान सतरकता से और धीरे-धीरे आगे बढ़े।



भूटान-चीन के बढ़ते संबंधों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

■ सुरक्षा नहितारथ:

- भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव भारत के सुरक्षा हतियों के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं, वशीष रूप से डोकलाम पठार क्षेत्र में जो भारत, भूटान और चीन के त्रिमिट्रिंग (tri-junction) पर स्थिति एक रणनीतिक क्षेत्र है।
 - भारत और चीन के बीच [डोकलाम को लेकर वर्ष 2017 में तनावपूरण](#) गतरिधि की स्थितिबिनी थी, जब भारतीय सैनिकों ने भूटान के दावे वाले विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा सङ्क नरिमाण को रोकने के लिये हस्तक्षेप किया था।
- यदि चीन और भूटान एक सीमा समझौते पर पहुँचते हैं जिसमें डोकलाम भी शामिल होगा तो यह [सलीगुड़ी कॉरडोर](#)—जसे 'चकिन नेक' (Chicken's Neck) के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की पहुँच को खतरे में पहुँचा सकता है।
- भारत एक बफर राज्य के रूप में भूटान पर अपना प्रभाव भी खो देगा और उसे चीन एवं पाकिस्तान के साथ संभावित दो-मोरचा युद्ध परदीश्य से नपिटना होगा।

■ आर्थिक नहितारथ:

- भूटान और भारत के बीच एक सुदृढ़ आर्थिक साझेदारी मौजूद है, जो मुख्य रूप से [जलविद्युत सहयोग](#) पर आधारित है।
 - भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवाश (FDI), सहायता (aid) और ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है।
 - भारत भूटान की अधिकांश अधिकारियों द्वारा आयात करता है, जो भूटान के राजस्व का लगभग 40% है।
- यदि भूटान चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाता है तो इससे भारत पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

■ कूटनीतिक नहितारथ:

- भूटान और भारत के बीच एक विशिष्ट संबंध है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों पर आधारित है।
 - भारत वर्ष 1949 से ही भूटान का निकटतम सहयोगी और संरक्षक देश रहा है, जब दोनों देशों के बीच एक संधि (भारत-भूटान शांतिएवं मतिरत्न संधि, 1949) पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि ने भारत को भूटान की विदेशी नीति और रक्षा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान किया।
- हालाँकि [भूटान को अधिक सवायत्तता देने के लिये वर्ष 2007 में इस संधि](#) को संशोधित किया गया था, फरि भी भारत भूटान के विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका नभिता है।
- यदि भूटान चीन के साथ औपचारिक राजनयकि संबंध स्थापित करता है तो यह उसकी पारंपरिक भारत समरथक विदेशी नीति को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्र में भारत के प्रभाव को चुनौती दे सकता है।

■ अवसंरचना और कनेक्टिविटी:

- यदि भूटान चीन के 'बेलट एंड रोड इनशिरिट्वि' (BRI) में भागीदारी करता है तो इसका क्षेत्रीय अवसंरचना विकास और कनेक्टिविटी पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत BRI के रणनीतिक और सुरक्षा नहितारथों को लेकर चति रखता है।

■ क्षेत्रीय संगठनों में प्रभाव:

- चीन के साथ भूटान का संरेखण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बंगल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है।

भूटान और चीन के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारत को कसि प्रकार आगे बढ़ना चाहयि?

- कूटनीतिमें संलग्न होना:** भारत को चीन के साथ भूटान के विकासित होते संबंधों को समझने के लिये भूटान के साथ कूटनीतिक संलग्नता बनाए रखनी चाहयि। भरोसा बनाए रखने और भूटान की कर्सी भी चति का समाधान करने के लिये खुला एवं पारदर्शी संचार महत्वपूर्ण है।
- सीमा वारता पर सहयोग करना:** भारत को सीमा वारता पर भूटान के साथ मिलकर कार्य करना चाहयि। एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा समझौता जो उत्तर में भूटान की चतिओं को संबोधित करे, जबकि पश्चिम में भारत के हतिं को संरक्षित करे, दोनों पक्षों के लिये लाभप्रद स्थिति हो सकती है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मतिरता को प्रगाढ़ करेगा।
- भूटान के प्रपिक्षय को समझना:** चीन के साथ संबंधों के विकास में भूटान के तरक और प्रेरणा को भारत द्वारा समझे जाने का प्रयास करना चाहयि। इसमें आर्थिक विकास एवं सुरक्षा के लिये भूटान की इच्छा को समझना और यह स्वीकार करना शामिल है कि वह अपने हतिं के लिये चीन के साथ संलग्नता को बढ़ा सकता है।
- विश्वास निर्माण:** भारत को यह विश्वास होना चाहयि कि एक विश्वसनीय पड़ोसी के रूप में भूटान, चीन के साथ अपने संबंधों के बारे में निरिण्य लेते समय अपने हतिं के साथ-साथ भारत के हतिं पर भी विचार करेगा। क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इस प्रस्पर विश्वास का निर्माण आवश्यक है।
 - भूटान के प्रधानमंत्री पहले ही भारत को आश्वस्त कर चुके हैं कि चीन के साथ कसि भी समझौते में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भारत के हतिं को क्षति न पहुँचे।
- एक मज़बूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना:** भारत को विकास सहायता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना जारी रखना चाहयि। मतिरता के ये बंधन दोनों देशों के हतिं को आगे और संरेखित करेंगे।
- क्षेत्रीय सहयोग:** भारत को प्रयावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और व्यापार जैसी आम क्षेत्रीय चुनौतियों से नपिटने के लिये भूटान, भारत एवं चीन को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय सहयोग के रास्ते तलाशने चाहयि।

नष्टिकरण

चीन के साथ भूटान के बढ़ते संबंधों का भारत के रणनीतिक हतिं, अरथव्यवस्था और क्षेत्रीय प्रभाव के लिये जटिल नहितिरथ हैं। भारत की प्रतिक्रिया में सुरक्षा, आर्थिक विधिकरण और क्षेत्रीय कूटनीतिको प्राथमिकता देते हुए एक नाजुक संतुलन लाने की आवश्यकता है। भूटान के साथ सुदृढ़ संबंध बनाए रखकर, खुली बातचीत में शामिल होकर और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत अपने रणनीतिक पड़ोस में अपने हतिं को संरक्षित करते हुए इन उभरती गतशीलताओं के बीच प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत की सुरक्षा, अरथव्यवस्था और क्षेत्रीय प्रभाव पर चीन के साथ भूटान के बढ़ते संबंधों के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिये। भारत को अपने पड़ोस में इन उभरती गतशीलताओं पर रणनीतिक रूप से कसि प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहयि?